तैयारी | कानपुर रिंग रोड और शाहजहांपुर-शाहाबाद बाईपास का काम भी इन परियोजनाओं में शामिल, 11905 करोड़ रुपये लागत आएगी

यूपी में हाईवे की सात नई परियोजनाएं शुरू होंगी

■ हेमंत श्रीवास्तव

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) पश्चिमी यूपी के कार्यक्षेत्र में आने वाले मध्य व पश्चिमी यूपी में जल्द ही सात नई परियोजनाओं का निर्माण कार्य शुरू कराने जा रहा है। इन परियोजनाओं की कुल लंबाई 283 किमी. है। जिसकी लागत 11905 करोड़ रुपये है। कानपुर रिंग रोड, शाहजहांपुर-शाहाबाद बाईपास, मथुरा-हाथरस-बदायूं-बरेली तथा मुरादाबाद-ठाकुरद्वारा फोर-सिक्स लेन का काम इन परियोजनाओं में प्रमुखता से शामिल हैं।

एनएचएआई से मिली जानकारी के मुताबिक शाहजहांपुर से शाहाबाद बाईपास फोर लेन बनाया जाना है। इसके पैकेज 2-ए के टेंडर को स्वीकृत किया गया है। इसकी कुल लंबाई 34.9 किमी. और परियोजना की कुल लागत 947.74 करोड़ रुपये है। इसी तरह कानपुर रिंग रोड एनएचडीपी फेज-एक का टेंडर भी हो गया है। इसकी लंबाई 24.559 किमी तथा लागत 1796 करोड़ रुपये है।

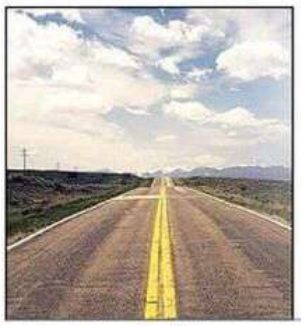

> इन परियोजनाओं की टेंडर प्रक्रिया पूरी करने के साथ कांट्रैक्टर को लेटर ऑफ इंटेट जारी किया गया है। तीन-चार माह में काम शुरू होगा। दो साल के अंदर परियोजनाओं को पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है।
>
> **संजीव शर्मा**, रिजनल आफिसर, एनएचएआई यूपी वेस्ट

बरेली-पीलीभीत-सितारगंज मार्ग बनेगा फोर-लेन : बरेली-पीलीभीत-सितारगंज सेक्शन के पैकेज एक का फोर-लेन काम भी होना है। इस परियोजना की लंबाई 32.5 किमी तथा लागत 1391.64 करोड़ रुपये है। इसी मार्ग के पैकेज दो का काम भी किया जाना है।

दो परियोजनाओं का काम ईपीसी मोड पर

इनमें से कानपुर रिंग रोड और मुरादाबाद-ठाकुरद्वारा हाइवे का निर्माण कार्य ईपीसी मोड पर होना है। टेंडर प्रक्रिया पूरी करने के साथ ही लेटर आफ इंटेट जारी कर दिया गया है। ईपीसी मोड के तहत इस परियोजना की लागत सरकार वहन करेगी।

बिल्ट, आपरेट, ट्रांसफर मॉडल पर पांच परियोजनाएं

शाहजहांपुर-शाहाबाद बाईपास, बरेली-पीलीभीत-सितारगंज फोर लेन, मथुरा-हाथरस-बदायूं-बरेली फोर लेन का काम एचएएम मोड पर होना है। इस काम में 40 फीसदी लागत सरकार वहन करेगी तथा शेष 60 फीसदी लागत विकासकर्ता खर्च करेगी। विकासकर्ता द्वारा 60 फीसदी खर्च की जाने वाली धनराशि बिल्ट आपरेट एंड ट्रांसफर पर आधारित है। जिसके तहत विकासकर्ता सड़क बनाएगा, उसे आपरेट कर टोल वसूलेगा और फिर अनुबंध के तहत निश्चित अवधि पर इसे प्राधिकरण को ट्रांसफर करेगा।